भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1168

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

एकीकृत भुगतान इंटरफेस की सफलता

1168. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल: डॉ. के सुधाकरः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः श्री यदुवीर वाडियारः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः डॉ. हेमांग जोशीः
श्री पी.पी चौधरीः श्री पी.सी मोहनः
श्री जी. सेल्वमः श्री सी.एन. अन्नादुरईः
श्री बिभु प्रसाद तराईः श्री शिवमंगल सिंह तोमरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने विशेषकर लेनदेन के परिमाण के संदर्भ में अन्य प्रमुख वैश्विक तत्काल भुगतान प्रणालियों/गेटवे को कितना पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यूपीआई की अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय तत्काल भुगतान प्लेटफार्मों की तुलना में वर्तमान स्थिति क्या है और बाजार हिस्सेदारी को दर्शाने वाला विस्तृत तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी पहलों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में यूपीआई प्लेटफार्म पर शामिल हुए नए व्यापारियों और छोटे व्यवसायों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) तमिलनाडु में रुपे से जुड़े खातों के माध्यम से किए गए यूपीआई लेनदेन की मात्रा और इसका मूल्य कितना है;

(ङ) देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश के देवास शाजापुर और राजस्थान के पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में छोटे व्यापारियों के बीच यूपीआई को अपनाने को बढ़ावा देने संबंधी प्रमुख सरकारी योजनाएं क्या हैं और उनका प्रभाव क्या है;

(च) विशेषकर तमिलनाडु में टियर-दो और टियर-तीन के शहरों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या सरकार का विशेषकर तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक सेवाओं, परिवहन और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ रुपे और यूपीआई प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए किसी नई पहल का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) और (घ): जून 2025 की 'बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान (अंतःप्रचालनीयता का मूल्य)' पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को लेनदेन की मात्रा के मामले में विश्व की सबसे बड़ी खुदरा फास्ट-पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) के रूप में मान्यता दी थी। इसके अलावा, 'प्राइम टाइम फॉर रीयल-टाइम' 2024 पर एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली लेनदेन की मात्रा में यूपीआई की लगभग 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

अन्य अग्रणी अंतरराष्ट्रीय रीयल-टाइम भुगतान प्लेटफार्मों की तुलना में यूपीआई की वर्तमान स्थिति और बाजार हिस्सेदारी को दर्शाने वाली विस्तृत तुलना अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग), (च), (छ) और (ज): यूपीआई सहित डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने में लघु व्यापारियों की सहायता करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा समय-समय पर विभिन्न पहल की गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना और भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) शामिल है जो टियर-3 से 6 केंद्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना (जैसे पीओएस टर्मिनल और क्यूआर कोड) के परिनियोजन के लिए बैंकों और फिनटेक को अनुदान सहायता प्रदान करती है। 31 अक्टूबर, 2025 तक, पीआईडीएफ के माध्यम से टियर-3 से 6 केंद्रों में लगभग 5.45 करोड़ डिजिटल टच प्वाइंट परिनियोजित किए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, लगभग 6.5 करोड़ व्यापारियों के लिए कुल 56.86 करोड़ क्यूआर परिनियोजित किए गए थे।

(ङ): एनपीसीआई ने सूचित किया है कि यूपीआई से संबद्ध रुपे खातों द्वारा शुरू किए गए लेन-देनों का विभाजन को अलग से नहीं लिया जाता है। हालांकि, तमिलनाडु राज्य द्वारा अक्टूबर 2025 में 1.28 लाख करोड़ रुपये मूल्य के साथ 81.20 करोड़ यूपीआई लेनदेन का योगदान दिया गया है।

(छ): सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई ने तमिलनाडु राज्य सहित राष्ट्रव्यापी आधार पर सार्वजनिक सेवाओं, परिवहन और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों सहित कारोबारों में रुपे और यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को व्यापक पैमाने पर करने की शुरुआत की है।

अनुबंध-I

अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रीयल-टाइम भुगतान प्लेटफार्मों की तुलना में यूपीआई की स्थिति

देश	लेन-देन की मात्रा (बिलियन में)	वैश्विक वास्तविक समय भुगतान प्लेटफॉर्म का हिस्सा %
भारत	129.3	49%
ब्राजील	37.4	14%
थाईलैंड	20.4	8%
चीन	17.2	6%
दक्षिण कोरिया	9.1	3%
अन्य	52.8	20%
कुल	266.2	100%

स्रोत: 'प्राइम टाइम फॉर रीयल-टाइम' 2024 पर एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट

*****